मोदी के रोजगार जुमलों को मोहन भागवत का संघ पूरा करेगा?

पानीपत-समालखा (मजदूर मोर्चा) आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत की इच्छा पूरी करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर ने यहां करीब 800 करोड़ की लागत से एक विशाल एवं भव्य संघ भवन का निर्माण कराया। बीते सप्ताह इसी भवन में देश भर से आये करीब 1400 संघियों का दो दिवसीय शिविर चला। शिविर के भीतर कैसे-कैसे साम्प्रदायिक षड्यंत्रों पर विचार किया गया, इसका तो पता नहीं चल पाया। लेकिन संघ ने जो घोषणा की है वह बहुत ही 'शानदार' है।

प्रति वर्ष दो करोड़ नौकरियां देने का वायदा करने वाले मोदी ने नौकरियां तो क्या देनी थी, उन्हें समाप्त करने पर ही जुटे हैं। उनके इस चुनावी जुमले को हकीकत का रूप देने की घोषणा करते हुए कहा गया है कि देश भर के 700 ज़िलों में रोजगार सृजन केन्द्र स्थापित करेगा संघ। बड़ी अजीब घोषणा है। इसमें कोई स्पष्ट बात नहीं कही गई है कि इन सृजन केन्द्रों से कितने रोजगार मिलेंगे और कब मिलेंगे? मामला गोल-मोल है। लगता है कि यह केवल घोषणा के लिये ही घोषणा है। जो सर्वशक्तिमान प्रधानमंत्री मोदी कोई रोजगार न दे सका और पकौड़े तलने का विकल्प युवाओं को दिया, उसके मुकाबले संघ के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है कि वह रोजगार पैदा कर देगा? अगर वास्तव में ही इनके पास ऐसी कोई जादुई छड़ी है तो बीते 98 साल तक वह छड़ी कहां छिपी थी?

घोषणा में रोगमुक्त व अपराधमुक्त समाज का निर्माण किया जायेगा। रोगमुक्ति के लिये मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड तथा खट्टर जी ने इससे भी आगे बढ़कर चिरायु कार्ड और अतिरिक्त रूप से दे दिये हैं। इसके साथ-साथ कोई भी मरीज़ किसी भी समय टेलीफोन पर डॉक्टरों से अपना मुफ्त इलाज करा सकता है। इतनी 'भारी-भरकम सुविधायें' देने के बाद रोग रह कहां पायेगा? इसी के मद्देनजर खट्टर सरकार ने अपने तमाम मेडिकल कॉलेजों आधे से अधिक पद रिक्त रखे हुए हैं। इससे भी बद्तर स्थिति राज्य भर के तमाम अस्पतालों की है। ऐसे में संघ, इस दिशा में और क्या योगदान देना चाहेगा?

रही बात अपराध मुक्त समाज की तो जब सारे अपराध करने का ठेका खुद संघियों ने ही ले रखा हो तो किसी और को अपराध करने का मौका ही कहां बचा है? फ़िर भी किसी को अपराध जगत में प्रवेश पाना हो तो इसके लिये संघियों के बजरंग दल, गौ-रक्षक दल , हिन्दूवाहिनी आदि-आदि मौजूद हैं। इनमें शामिल होकर अपराध करने वालों को पुलिस का पूरा संरक्षण प्राप्त होता है।

एक वायदा ऋणमुक्त करने का भी घोषित किया गया है। इसे पूरा करने के लिये मोदी जी ने तमाम बड़े कार्पोरेट विशेषकर अडाणी के लिये अपने बैंकों के दरवाजे खोल रखे हैं। बीते 9 वर्षों में इनके करीब 12 लाख करोड़ तथा अकेले अडाणी के ढाई लाख करोड़ माफ़ करके उन्हें काफी हद तक ऋणमुक्त कर दिया गया है। रही-सही कसर मोदी जी शीघ्रातिशीघ्र पूरी करने जा रहे हैं। ऐसे में संघ वाले भला किसको ऋणमुक्त करने का झांसा दे रहे हैं?

घोषणा में संघ का अधिकतम ध्यान केरल पर केन्द्रित रहा। सर्वविदित है कि इस राज्य में अभी तक संघ की कोई तिकड़मबाजी सफल नहीं हो पाई है। संघियों की हर गुंडागर्दी का जबाब उन्होंने उन्हीं की भाषा में सही-सही दे रखा है। संघियों के हर हमले का जबाब वहां के प्रबुद्ध नागरिक ठोक कर देते आये हैं।

नगर निगम के भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल रही सीएम विंडो की प्रख्यात नागरिक!

भ्रष्टाचार की शिकायत करने वाले व्हिसल ब्लोअर पर लगाया निजी स्वार्थ का आरोप, सीएम विंडो से ब्लैकलिस्ट करने की सिफारिश की

फरीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली खट्टर सरकार के नुमाइंदे ही नगर निगम में मची लूट-खसोट और भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने में जुटे हैं। विज्ञापन विभाग में चल रही धांधली की शिकायत करने वाले व्हिसल ब्लोअर को सीएम विंडो की प्रख्यात नागरिक ने ब्लैकमेलर बता कर शिकायत बंद करवा दी। इससे आहत पीड़ित ने सीएम विंडो पर प्रख्यात नागरिक के खिलाफ शिकायत दर्ज करा कार्रवाई की मांग की है।

मुजेसर निवासी दीपक गोदारा नगर निगम की विज्ञापन शाखा में अनुबंध कर्मचारी रह चुके हैं। उनके अनुसार ड्यूटी के दौरान उन्होंने पाया कि प्रतिबंध के बावजूद मोबाइल वैन और पोल कियॉस्क पर विज्ञापन लगाए जा रहे हैं और इनसे होने वाली लाखों रुपयों की कमाई की बंदरबांट हो रही है, जबकि निगम के खजाने में कुछ नहीं जा रहा। इसी तरह गैंट्री और यूनीपोल भी निर्धारित संख्या से कहीं अधिक लगवा कर मोटी कमाई की जा रही है। उन्होंने इसका विरोध किया तो उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं।

उन्होंने भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए सीएम विंडो पर 30 दिसंबर 2022 को इसकी शिकायत दर्ज कराई। निगम के अधिकारियों ने शिकायत में दर्शाए गए बिंदुओं का जवाब नहीं दिया और विद्वेष की भावना से शिकायत करने का आरोप लगाया।

सीएम विंडो की प्रख्यात नागिरक रीता गोसाईं ने भी दीपक पर निजी स्वार्थ में आरटीआई लगाने और सीएम विंडो पर शिकायत करने का आरोप लगाते हुए उसे ब्लैकलिस्ट करने की सिफारिश कर दी।

दीपक गोदारा का आरोप है कि भाजपा में विभिन्न ओहदों पर रह चुकीं रीता गोसाईं ने शिकायत के बारे में उनसे एक बार भी संपर्क नहीं किया और निगम अधिकारियों की मिलीभगत से उनके खिलाफ मनगढ़ंत रिपोर्ट तैयार कर भेज दी।

शिकायत की जांच तक नहीं की गई। उन्होंने सीएम विंडो पर फिर से आवेदन किया है कि यदि उनकी शिकायत गलत पाई जाए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, यदि सही हो तो प्रख्यात नागरिक रीता गोसाईं के खिलाफ पद का दुरुपयोग करने की कार्रवाई की जाए।

24 आरटीआई लगाईं लेकिन नहीं मिला जवाब

नगर निगम की विज्ञापन शाखा में कितना भ्रष्टाचार व्याप्त है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दीपक गोदारा 24 आरटीआई लगा चुके हैं लेकिन अधिकारियों ने जवाब नहीं दिया। आरटीआई का जवाब नहीं दिए जाने की शिकायत उन्होंने दो बार सीएम विंडो पर भी की लेकिन कार्रवाई के नाम पर उन्हें ही आरटीआई और सीएम विंडो से ब्लैकलिस्ट किए जाने की तैयारी की जा रही है। यदि नगर निगम की विज्ञापन शाखा में सबकुछ ठीक है तो अधिकारियों को आरटीआई के जवाब देने में देर नहीं करनी चाहिए।

जिस आरटीआई कार्यकर्ता एवं पूर्व निगम कर्मचारी गोदारा को ब्लैकलिस्ट करने की चर्चा चल रही है आखिर उसने पूछा ही क्या है? यही न कि कितने विज्ञापन लग रहे हैं और निगम की कितनी आय हो रही है। यदि निगम अधिकारी इस धंधे में मोटी डकैती नहीं मार रहे तो हिसाब किताब क्यों नहीं सार्वजनिक करते? रही बात रीता गोसाईं की तो उन्हें इन लुटेरे अधिकारियों द्वारा अपने पक्ष में करना क्या मुश्किल है।

पूछने पर दीपक गोदारा ने बताया कि उन्होंने 21 दिसंबर 2021 को राज्य सूचना आयोग में दूसरी अपील की थी। जिसका आज तक जवाब नहीं आया, और अगले कई वर्षों तक आने की संभावना भी नहीं है।

प्रदूषण बढ़ाने के बाद घटाने के उपकरण खरीदने की तैयारी, यानी एक और घोटाला

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) शहर में बढ़ते प्रदूषण के जाने-माने कारणों को दूर करने की अपेक्षा वायु शोधक उपकरणों की खरीदारी की योजना बनाई जा रही है। नगर निगम कार्यालय के पीछे बने सभागार परिसर में एक एंटी स्मॉग गन पहले से ही खड़ी है जिसका कोई लाभ नज़र नहीं आया। यह मशीन हवा में पानी का स्प्रे करके धूल कणों को नीचे गिराने के लिये लगाई गई थी। अब स्मार्ट एयरबिन (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) नामक एक और नई मशीन लगाने जा रहे हैं। इस पद्धति पर काम करने वाली यह मशीन 30 मीटर तक से जहरीली गैस और धूल कण आदि को सोख कर हवा को शुद्ध कर देगी।

25 लाख की लागत वाली यह मशीन शुरुआती तौर पर किसी व्यस्त चौराहे पर लगाने की योजना है। इसकी सफलता एवं गुणवत्ता का आकलन करने के बाद ऐसे ही अन्य कई स्थानों पर इसे लगाया जायेगा। जैसा कि बताया जा रहा है, यह उपकरण मात्र 30 मीटर तक की परिधि की वायु का शोधन कर पायेगा। अब सवाल यह पैदा होता है कि 25 लाख से अधिक आबादी वाले इस लम्बे-चौड़े शहर में ऐसे कितने उपकरण लगाने पड़ेंगे अथवा ऐसे उपकरण केवल वीआईपी क्षेत्रों में ही लगाये जायेंगे?

शासकवर्ग सारी जनता को वायु प्रदूषण से राहत दिलाने की अपेक्षा केवल कुछ चुनिंदा लोगों को ही शुद्ध हवा उपलब्ध कराने की बात तो सोच ही रहा है, साथ में नये-नये उपकरण खरीदने के नाम पर जो लूट कमाई होगी वह उनका बोनस होगा।

यदि शासक वर्ग को वास्तव में ही प्रदूषण मुक्त वायुमंडल बनाना होता तो वह उन कारकों को दूर करता जिनके चलते वायु प्रदूषण हो रहा है। सड़कों से उड़ने वाली धूल, बिल्डरों द्वारा निर्माणाधीन इमारतों पर नियमों का पालन न करने से उड़ने वाली धूल, सड़कों पर लगने वाले जाम से होने वाला अतिरिक्त वायु प्रदूषण बहुत आसानी से रोका जा सकता है, बशर्ते कि रोकने वालों की नीयत साफ़ हो।

इसी तरह फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं को भी रोका जा सकता है यदि सरकार उन्हें पर्याप्त मात्रा में बिजली तथा उचित दामों पर वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध कराये। महंगी घरेलू गैस के चलते लोगों को जो वैकल्पिक ईंधन जलाना पड़ता है वह भी प्रदूषण को बढ़ाता है। निकम्मे एवं भ्रष्ट प्रशासन की कोताही के चलते जगह-जगह कूड़े के ढेरों को जलते हुए देखा जा सकता है। शासकवर्ग अपनी इस कुव्यवस्था को सुव्यवस्था में बदलने की बजाय वे सब काम करता है जिससे जनता को कोई लाभ नहीं और उसे लूट कमाई का लाभ होता रहे।

नाकारा प्रदूषण नियंत्रण विभाग

वायु प्रदूषित करने के जो-जो भी कारक सामने हैं उनमें से किसी को भी दूर करने की क्षमता इस विभाग में नहीं है, यह केवल जुर्माने एवं रिश्वत के रूप में वसूली मात्र ही कर सकता है। लगभग यही दशा एनजीटी (नेशनल ग्रिन ट्रिब्यूनल) की भी है। ये दोनों ही उपक्रम केवल लेन-देन की दुकानों से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इनके अस्तित्व में आने के बाद किसी भी प्रकार के प्रदूषण में कोई कमी आना तो दूर, लगातार बढता ही जा रहा है। हां, यह विभाग एक 'अच्छा' काम केवल यह बता कर कर रहा है कि वायु कितनी प्रदूषित हो गई है।

वायु प्रदूषण के अतिरिक्त कपड़ा रंगने वाली तथा ऐसी ही कई अन्य इकाइयां भू-जल को भी लगातार प्रदूषित किये जा रही हैं। ये इकाइयां गंदा एवं खतरनाक रसायनयुक्त पानी सीधे बोरवैल के जरिये धरती में इंजेक्ट कर देती हैं। बीते सप्ताह ऐसी ही करीब 20 इकाइयों को इस विभाग ने बंद कराया है। ऐसी इकाइयों को बंद कराने का उपक्रम हर दो-चार महीने बाद होता रहता है। भू-जल प्रदूषित करने वालों के लिये क्या इतनी सज़ा ही काफ़ी है? इनके विरुद्ध आपराधिक धाराओं में मुकदमा क्यों नहीं चलाया जाता?

दूसरा बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि क्या प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों को सील करने अथवा उनसे वसूली करने के लिये ही प्रदूषण नियंत्रण नाम का यह विभाग पाल रखा है जिस पर करदाता का करोड़ों रुपया बर्बाद किया जा रहा है? यही काम इलाके का तहसीलदार व थानेदार कही अधिक बेहतर ढंग से कर सकता है।